has established a camp office at Jammu due to growing militant activities in Kashmir Velley.

(b) Chief General Manager is performing his duties of operation & maintenance of Telecom. Services in J & K.

(c) and (d) At present it is proposed to continue the camp office at Jammu.

डाक और तार सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2934. **श्री गोविन्दराम मिरीः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने डाक और तार सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की किस सीमा तक आमंत्रित किया है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने में अधिक रुचि दिखाई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार की अद्यतन योजना क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ):

डाक विभाग (क) सरकार ने डाक सेवाएं प्रदान करने में निजी क्षेत्रों की सहभागिता आमंत्रित नहीं की है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार विभाग:

(क) से (ग) सरकार ने बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए 21 दूरसंचार सर्किलों में निजी क्षेत्र की सहभागिता आमंत्रित की है। इनमें से छह कंपनियों ने छह सर्किलों के लिए पहले ही लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जहां तक मूल्यवर्धित सेवाओं का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि चार महानगरों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालन के लिए 8 लाइसेंसधारक कंपनियों को 8 लाइसेंस दिए गए हैं तथा 8 क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किलों के लिए 14 कंपनियों को 34 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। 54 शहरों में पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा के प्रचालन के लिए 25 कंपनियों को, ई-मेल के प्रचालन के लिए 15 कंपनियों को, वायस मेल/आडियो टेक्स सेवा के प्रचालन के लिए 14 कंपनियों को तथा इनसेट उपग्रहों के माध्यम से 64 केबीपीएस क्लोज्ड यूजर ग्रुप डोमेस्टिक डाटा वी-सेट सेवा के प्रचालन के लिए 12 कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं। रेडियो पेजिंग सेवा के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि 27 बड़े शहरों के लिए 17 भारतीय पूंजीकृत कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। 18 दूरसंचार सर्किलों में 11 कंपनियों को 31 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

जहां तक विलेज पब्लिक टेलीफोन (वीपीटी) का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि बुनियादी टेलीफोन सेवा में निविदा/लाइसेंस की शर्त के अनुसार, बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने वाली लाइसेंसधारक कंपनी के लिए लाइसेंस अवधि के पहले तीन वर्षों में तिमाही आधार पर सीधी एक्सचेंज लाइनों की कम से कम 10 प्रतिशत लाइनें वीपीटी के लिए प्रदान करनी अपेक्षित हैं।

किसी भी मूल्यवर्धित सेवा लाइसेंस/रेडियो पेजिंग सेवा में ग्रामीण क्षेत्र कवर करने की कोई अनिवार्य शर्त नहीं है।

डाक विभाग:

(घ) ग्रामीण क्षेत्र में डाक सेवा को, डाक नेटवर्क के विस्तार, मनीआर्डरों का उपग्रह के माध्यम से पारेषण द्वारा तथा वितरण प्रणालियों में सुधार लाकर सुदृढ़ बनाया जाना है।

दूरसंचार विभाग:

(घ) सर्किलों में बुनियादी सेवाओं के लिए 6 दूरसंचार सर्किलों के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। योजनावधि के दौरान निजी आपरेटरों द्वारा इन सर्किलों में लगभग 68,000 गांवों को सेवा प्रदान करने की संभावना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

(i) आंध्र प्रदेश सर्किल		:	6222
(ii) गुजरात सर्किल		:	4202
(iii) मध्य	प्रदेशप्रथम वर्ष	:	5500
सर्किल—	द्वितीय वर्ष	:	5500
	तृतीय वर्ष	:	3000 (अनंतिम)

(iv) महाराष्ट्र सर्किल—	प्रथम वर्ष	:	400
	द्वितीय वर्ष	:	10080
	तृतीय वर्ष	:	383
(v) पंजाब —		:	776
(vi) राजस्थान	प्रथम वर्ष	:	0
सर्किल—	द्वितीय वर्ष	:	7439
	तृतीय वर्ष	:	8151

बिहार सर्किल से संबंधित लाइसेंस में 11100 वीपीटी के लिए हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

दूरसंचार विभाग 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रत्येक गांव में एक सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की न्यूनतम दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

M.T.N.L. Promise to give Telephone Connections

2935. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that M.T.N.L. has invited applications for telephone connections with last date as February 7, 1998 with the promise that connections will be given March 31, 1998;

(b) if so, how many such applications have been received and how many connections have been given; and

(c) whether M.T.N.L. was able to fulfil the promise, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) Yes, Sir.

In MTNL Delhi, the last date upto which applications were invited was 06-02-1998 and not 07-02-1998.

In MTNL Mumbai advertisement were issued during January, February, March, 1998 to provide telephone connections in technically feasible areas only as per details given belwo:—

Booking by	Telehpone Connections to be provided by
31-01-1998	28-02-1998
28-02-1998	31-03-1998
March, 1998	31-03-1998

(b) the details of the applications received and telephone connections provided by MTNL are given below:

(i) MTNL Delhi
No. of applications received 14,763
No. of telephone connections provided 11,633

(ii) MTNL Mumbai
No. of applications received 1,04,055
No. of telephone connections provided 95,444
(feasible cases only)

(c) Yes, Sir.

MTNL Mumbai was able to fulfil the promise of providing telephone connections for feasible cases.

However, MTNL Delhi could fulfil the promise for 78.7% cases. 3103 applicants could not be provided telephone connection due to non-completion of cable construction job in some pockets/ areas of different telephone exchange due to reasons beyond control.

Telephone Advisory Committee for Mumbai

2936. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government has constituted Telephone Advisory Committee for metropolitan city Mumbai;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether Government are aware of the fact that for more than six months there is no T.A.C. in Mumbai; and

(d) by when it is likely to be constituted?